

कार्यसूची सं.	1
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक सं.	67

दिनांक 15 फ़रवरी, 2019 को आयोजित 66 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक 15 फ़रवरी, 2019 को आयोजित 66 वीं त्रैमासिक SLBC बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं।
- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक सं.	67

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	वर्तमान स्थिति
1	15.06.2018	Dedicated Certificate Officer की नियुक्ति का मामला	Dedicated Certificate Officer एवं अन्य कर्मचारियों के कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा किये जाने के राज्य सरकार के सुझाव के अलोक में बैंको द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को पत्रांक SLBC/18-19/53 दिनांक 15.06.2018 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था, जिसमे बैंकों द्वारा वसूली गयी राशि से 5% की राशि सरकारी कोष में जमा करने की सहमति दी गयी थी। पूर्व में तत्कालीन विकास आयुक्त के आदेशानुसार बैंको से पुनः इस पर परिचर्चा की गयी परन्तु व्यवहारिक कठिनायियों के कारण बैंको द्वारा कार्यालयीय खर्च की प्रतिपूर्ति कर पाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। किसी सर्वमान्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाने के कारण इस विषय को अगले बैठक से समाप्त कर दिए जाने का प्रस्ताव SLBC द्वारा पिछली बैठक के दौरान किया गया था परन्तु RBI के सुझाव के आधार पर इसे पुनः राज्य सरकार के पास लंबित मामलों में शामिल किया जा रहा है और सरकार से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में ज्यादा NPA वाले बैंको के नियंत्रक प्रमुखों के साथ बैठक कर कोई सर्वमान्य हल ढूंढा जाये।
2	23.07.2018	बैंको को सरकारी भूमि का आवंटन का मामला	राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में SLBC एवं अन्य बैंको को आवंटित किये जाने वाली भूमि के क्रय मूल्य में किये गए परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा हेतु विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित था परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कोई बैठक नहीं हो पाई है।
3	27.11.2017	SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए लंबित cases	बैंको से SLBC के पोर्टल पर प्राप्त सूचना बैंको द्वारा ऋणियों के नाम के साथ दिए गए जिलावार सूचना से काफी भिन्न है। SLBC द्वारा नाम के साथ दी गयी pending रिपोर्ट की सूची राज्य सरकार को दिनांक 07.05.2019 दी गयी है।
4	23.07.2018	land records को अद्यतन किया जाना	राज्य में land records को अद्यतन (dizitization) किये जाने के बावजूद इसके regular updation नहीं किये जाने के कारण वास्तविक जमीन मालिक के सही पहचान में आ रही कठिनाई के समाधान हेतु राज्य सरकार से सहयोग अपेक्षित है।

5	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों में नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराये जाने के मुद्दे को RBI के सुझाव के आलोक में पुनः शामिल किया जा रहा है और इस विषय पर सरकार से वर्तमान वस्तुस्थिति की जानकारी अपेक्षित है।
---	------------	---	--

बैंक से संबंधित मामले

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-3 (a) से 3 (f) पर संलग्न है।

कार्यसूची सं.	3
बैठक दिनांक	15.05.2019
बैठक सं.	67

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	31.03.2018	31.12.2018	31.03.2019	Bench Mark
1	Deposit	198114.26	210626.45	218100.64	
	CASA Deposit		97523.12	99896.90	
2	Credit	85518.63	94002.59	95562.14	
3	Credit as per place of utilization* & RIDF**	33957.45	32466.00	29465.43	
4	Total Credit	119476.08	126468.59	125027.57	
5	CD Ratio	60.31	60.04	57.33	60
6	Priority Sector Advances (PSA)	46528.36	50898.32	52924.75	
7	Share of PSA to Total Advances (%)	54.40%	54.15%	55.38%	40
8	Agricultural Advances	13485.92	14367.67	14864.80	
9	Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)	15.77%	15.28%	15.56%	18
10	i. Micro & Small Enterprises Advance	21711.74	21958.79	24189.37	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	25.38%	23.35%	25.31%	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	58.34%	56.94%	56.60%	
11	Advances to Weaker Sections	14852.75	15625.68	16334.11	
12	Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)	17.37%	16.62%	17.09%	10
13	DRI Advances	42.19	34.26	32.59	
14	Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)	0.05%	0.04%	0.04%	1
15	Advances to Women	11269.86	10503.06	13027.82	
16	Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)	13.18%	11.17%	13.63%	5
17	Advances to Minorities (Amount)	5620.21	5733.03	6113.46	
18	Share of Advances to Minorities under PSA (%)	12.08%	11.27%	11.55%	15
19	Gross N.P.A	5223.27	5657.68	5711.86	
	Provision	2790.54	2813.78	2820.73	
	Net NPA	2432.73	2843.90	2891.13	
	Gross NPA Percentage	6.10%	6.01%	5.98%	
	Net NPA Percentage	2.84%	3.02%	3.02%	
20	Branch Net-Work (in no.)-Rural	1497	1472	1486	
	Semi-Urban	785	752	776	
	Urban	726	783	834	
	Total	3008	3007	3096	
21	ATM installed in Jharkhand	3557	3347	3367	

*Annexure- V,

As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 31 मार्च, 2018 से 31 मार्च 2019 तक रूपये 19986.38 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है। वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 10.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में यानि 31 मार्च, 2018 से 31 मार्च 2019 तक रूपये 10043.51 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 11.75 प्रतिशत दर्ज की गई है।

ऋण – जमा अनुपात (C.D Ratio)

31 मार्च, 2018 की तुलना में 31 मार्च 2019 में CD ratio में कमी आई है, इसका मुख्य कारण SBI द्वारा core advances में लगभग रु 2200 करोड़ की कमी एवं place of utilization के अनुसार लगभग रु 3000 करोड़ की कमी है। बैंको के core CD ratio में भी पिछले तिमाही 44.63% की तुलना में कमी हुई है और यह घटकर मार्च 2019 में 43.82% हो गया है। सभी बैंकों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13.74% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 55.38 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र का o/s 14864. 80 करोड़ रु है जो कुल अग्रिम का 15.56 प्रतिशत है। यद्यपि पिछले वर्ष कृषि ऋण कुल अग्रिम का 15.77 प्रतिशत था, जिसमें वार्षिक आधार पर कमी हुई है परन्तु पिछले तिमाही की तुलना में कृषि ऋण जो कि कुल अग्रिम का 15.28% था, इसमें 0.28% की वृद्धि हुई है। कृषि ऋण का प्रतिशत कुल ऋण की तुलना में अभी भी राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से कम होने के कारण यह एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है। लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतु अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा।

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

31 मार्च 2019 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 16334.11 करोड़ (17.09 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

31 मार्च 2019 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रु. 13027.82 करोड़ है, जो कि कुल अग्रिम का लगभग 13.63 % है। यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है।

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रु 6113.46 करोड़ है। यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 11.55 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है। इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2019 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के MASTER CIRCULAR. No – FIDD.CO.LBS.BC.No. 1/02.01.001/2017-18, दिनांक 03.07.17 के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है :-

(Rs in crore)

DETAILS	31 st March, 2018	31 st March, 2019
Aggregate Deposits	198114.26	218100.64
CORE ADVANCES	85518.63	95562.14
Place of Utilization	29066.92	23147.97
RIDF	4890.53	6317.47
NET ADVANCES	119476.08	125027.57
CD Ratio	60.31	57.33

(परिशिष्ट- 4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि दिसम्बर 2018 की तुलना में बैंको के समग्र ऋण में वृद्धि हुई है परन्तु SBI के ऋण में आई कमी (लगभग रु 2200 करोड़) और जमा राशि में हुई वृद्धि के आधार पर हमारा core CD Ratio पिछली तिमाही के दौरान 44.63% से घट कर 43.82% हो गया है। इसके साथ ही SBI के place of utilization में हुई लगभग रु 3000 करोड़ की कमी के कारण राज्य का CD Ratio, 60.04 (पिछली तिमाही) से घट कर वर्तमान तिमाही में 57.33 रह गया है।

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक संख्या	67

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के तहत पूरे वित्तीय वर्ष में हुई उपलब्धियों की समीक्षा

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2017-18)	ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18		ANNUAL TARGET (2018-19)	ACHIEVEMENT IN AFY 2018-19	
	AMT.	AMT	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	7682.37	3757.56	48.91	8336.60	3824.82	45.88
MSME	7329.51	10337.95	141.05	8560.35	9285.95	108.47
OPS	3821.41	2132.47	55.80	4213.60	2171.67	51.54
Total Priority	18833.29	16227.98	86.16	21110.55	15282.44	72.39
Non Priority	8582.15	8605.03	100.26	8773.34	11744.84	133.87
Total	27415.45	24833.01	90.58	29883.89	27027.28	90.44

कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न बैंको एवं जिलों द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को क्रमशः पृष्ठ सं-7(a) एवं 7 (b) में दर्शाया गया है।

टिप्पणियां :

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 90.44 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है। यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष में हुई 90.58% संवितरण की तुलना में मामूली कम है, परंतु कुल प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण संवितरण में लगभग 14% की कमी अत्यंत चिंताजनक विषय है।
- कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के विरुद्ध केवल 45.88 % ऋण का संवितरण ही हो पाया है। कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में लगातार सुधार की आवश्यकता पर बल दिए जाने के बावजूद ऋण संवितरण में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3% की कमी आई है।
- MSME sector में इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा MSME के वार्षिक बजट के विरुद्ध 108.47% की उपलब्धि सराहनीय है, परन्तु इस क्षेत्र में भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 22% की कमी आई है।
- सभी बैंको द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण संवितरण पर अधिक focus किये जाने के बावजूद गैर प्राथमिकता वाले ऋण में हुई 33% की अप्रत्याशित वृद्धि पर बैंको के द्वारा समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

ANNUAL CREDIT PLAN 2019-20

- राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये नाबार्ड द्वारा प्रवर्तित “Potential Linked Plan” के व्यापक रूपरेखा के आधार पर “वार्षिक ऋण योजना” तैयार की गई।
- अग्रणी जिला प्रबंधक कार्यालयों के द्वारा तैयार इन “वार्षिक ऋण योजनाओं” को सभी जिलों के DLCC की बैठक में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। DLCC के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत ही वार्षिक ऋण योजनाओं को जिला स्तर पर अपनाया एवं लागू किया जाना है। प्रत्येक LDM के द्वारा SLBC को आश्वासन दिया गया है कि उनके द्वारा सअम्प्रेषित वार्षिक ऋण योजनाओं में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की संभावना नहीं है और इसलिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के द्वारा सभी जिलों से प्राप्त इन “वार्षिक ऋण योजनाओं” को संकलित कर राज्य की “वार्षिक ऋण योजना” बनाई गयी है जिसे LDMs को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी LDMs से अनुरोध है कि इन योजनाओं को DLCC में अनुमोदित कराकर SLBC को अविलम्ब सूचित करें।
- सभी जिलों से प्राप्त वार्षिक ऋण योजनाओं के आधार पर राज्य के सभी बैंक एवं जिलों का “वार्षिक ऋण योजना” पृष्ठ संख्या- 8(a)-8(h) संलग्न है।
- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की कृषि उप-समिति के निर्णयानुसार “वार्षिक ऋण योजना” में कृषि के sub-sector का जिलावार लक्ष्य संलग्न है।

▪ (Amt. in Crores)

PRIORITY SECTOR ADVANCES (Disbursement Budget FY 2019-2020)					
Agriculture	MSME	ExportCredit	Education	Housing	
5750.29	9373.10	21.42	685.75	1629.67	
Social Infrastructure	Renewable Energy	Others	Total Priority Sector		
76.62	20.86	400.63	17958.34		
NON-PRIORITY SECTOR ADVANCES (Disbursement Budget FY 2019-2020)					
Agriculture	Education	Housing	Personal Loans	Others	Total Non-Priority Sector
75.82	255.83	1217.32	1377.81	6317.83	9244.62

Total Advances

(Disbursement Budget FY 2019-2020)

Priority Sector	Non Priority Sector	Total
17958.34	9244.62	27202.96

वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट RBI के मानदंडों के अनुसार LBS के फॉर्मेट के आधार पर तैयार किया गया है और अगले तिमाही से वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान हुए प्रगति प्रतिवेदन (Achievement) को इसी format के अनुसार प्रदर्शित किया जाना है। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से अनुरोध है कि अगले तिमाही से SLBC के पोर्टल पर इसी प्रारूप के अनुसार reporting किया जाना सुनिश्चित करें। SLBC के पोर्टल पर इससे सम्बंधित आवश्यक बदलाव किया जा रहा है।

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक संख्या	67

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत में ₹. 14864.80 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.56 % है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों, नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुनः बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए।

झारखण्ड में KCC की स्थिति

(Amt in Cr.)

Type of Banks	Disbursement during 2018-19		Outstanding In KCC A/Cs (As of 31.03.2019)	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	406395	1635.49	1299364	5025.43
Pvt. Banks	74205	289.94	46538	217.92
Total	480600	1925.43	1345902	5243.35
RRB	124497	466.34	367406	1608.64
Co-op Banks	1476	4.45	22450	43.19
Total	606573	2396.22	1735758	6895.18

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

- ❖ सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों में आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके। दिनांक 31.03.2019 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार कुल 1563529 eligible KCC खातों में से 1391603 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1359056 खातों में (98%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।
(विवरण पृष्ठ सं-9(a) एवं 9(b) में संलग्न है)
- ❖ प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या- 9 (c) एवं 9 (d) पर दर्शाया गया है।

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

(Accounts in thousands) (Amt in Cr.)

Sl. No.	Particular		Outstanding position as at the end of		
			March 2018	March 2019	
(1)	(2)		(3)	(4)	
MICRO & SMALL ENTERPRISES					
1	Micro Enterprises		Accounts	544	766
			Amount	12667.89	13692.46
2	Small Enterprises		Accounts	45	53
			Amount	9043.85	10496.91
3	Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)		Accounts	589	819
			Amount	21711.74	24189.37
MEDIUM ENTERPRISES					
4.	Total of Medium Enterprises		Accounts	09	09
			Amount	1857.59	2453.94
MSME					
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			Accounts	598	828
			Amount	23569.33	26643.31
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts (stipulation: 60%)	58.34%	56.60%
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	25.38%	25.31%

(MSME रिपोर्ट –annexure-9)

COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE) (Position as on 31.03.2019)

(A/C in 000, Amt in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		TOTAL	
A/C	Amt	A/C	Amt.
569	19175.02	141	8901.42

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 10 a में सलग्न है)

टिप्पणियां

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरुद्ध मार्च, 2019 में 56.60 % है।
- बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य में, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 5.69 लाख (लगभग) MSE ऋण खातों हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं। इनमें से 1.41 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 24.78 % खातों में CGTMSE कवरेज लिया गया है। इस सम्बन्ध में सभी बैंको से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा खातों में CGTMSE coverage लेने का प्रयास किया जाये।

5.2 (ख) “प्रधानमंत्री मुद्रा योजना”

दिनांक 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई। यह योजना मुख्यतः गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी। परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है।

बैंको द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इस योजना के अंतर्गत उन्हें दिए गए लक्ष्य रु 3239.39 करोड़ के विरुद्ध राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.18 से 31.03.19 तक) (राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	No.	AMT	No.	AMT.	No.	AMT.	No.	AMT.
Sanctioned	232183	616.09	55033	1249.70	11926	878.84	299142	2744.64
Disbursed	224572	605.30	54890	1140.78	11766	811.10	291228	2557.18

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में सभी बैंको एवं Micro Finance Institutions के द्वारा सम्मिलित रूप से इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है :

(राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	No.	AMT	No.	AMT.	No.	AMT.	No.	AMT.
Sanctioned	1306288	3562.71	112743	1986.43	18605	1439.04	1437636	6988.18
Disbursed	1298677	3411.03	112600	1911.70	18445	1376.43	1429722	6699.17

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-11(a) एवं 11(b) में सलग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	Male Beneficiaries	Out of total Beneficiaries, SC/ST Beneficiaries	Loan Sanctioned Amt (Rs in Cr)
264	237	27	38	65.37

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-11(c) में सलग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 31.03.18	As on 31.03.19				Total As on 31.03.19	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSE MENT DURING FY 2018-19
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	62166	67690	666	781	126	69263	53.43	9848
Amount (In crore)	2878.36	3262.34	27.11	24.42	1.90	3315.77		473.18

(Annexure-10)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान शिक्षा ऋण के तहत कुल 9848 खातों में 473.18 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई है।
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नहीं है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति (annexure -10 A) इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2018-19)			9848	473.18
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	4593	214.26	4300	105.87
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	1074	48.46	1045	24.33

5.4 आवास ऋण

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 31.12.18	31.03.2019				Total Up to 31.03.19	Growth in H/Loan Y-on-Y	Disburse ment in AFY 18-19
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	75972	75803	5369	915	0	82087	1286.81	14111

राशि	8053.64	8646.46	633.02	54.35	6.62	9340.45		2075.20
------	---------	---------	--------	-------	------	---------	--	---------

(रिपोर्ट –annexure-11)

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

31 मार्च 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 मार्च, 2018		% Share	31 मार्च, 2019		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
46528.36	5620.21	12.08%	52924.75	6113.46	11.55%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च 2019 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

31 मार्च, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	31 मार्च, 2019		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
85518.63	11269.86	13.18%	95562.14	13027.83	13.63%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

31 मार्च 2019 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2018		DRI Percentage in Net Credit	31 मार्च, 2019		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
81039.94	51.15	0.07%	85518.63	32.59	0.04%

(रिपोर्ट –annexure-12)

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रु. करोड़ में.)

31 मार्च, 2018		% achievement	31 मार्च, 2019		% achievement
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
85518.63	12968.55	15.16%	95562.14	11483.33	12.01%

5.6. Scheme for financing of Women SHG

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 255615 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 152051 खातों का credit linkage है, जिसमें कुल रु 1334.88 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रु 961.42 करोड़ है।

(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (31 मार्च, 2019 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March'18	Addition during AFY-18-19	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	200	63	263
No of Villages	15733	5607	21340
Total No of SHGs supported by SRLM	132531	60651	193182
Total families supported by SRLM	1597905	733367	2331272
No of SHG receiving R.F	55741	27446	83187
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	8328	4150	12478
No of SHG receiving CIF	33901	3141	37042
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	18983	1526	20509
No. of SHG credit linked with Banks	66166	34313	100929
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	49005.45	34313	83318.45

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 27301 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या 34313 बताई गई है।

(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-14 (a) एवं 14 (b) में दिया गया है।)

कार्यसूची सं.	6
बैठक की तिथि	15.05.2019
बैठक की संख्या	67

**वित्तीय समावेशन एवं
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)**

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	3724	454	Nil	3203	5241

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (a) & 15 (b)}

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
6202	5399	3318	1826	255

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (c)}

C. PMJDY के तहत 31.03.2019 तक खोले गए खातों की स्थिति

31.03..2019 तक खोले गए खातों की संख्या			PMJDY खातों में जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	B	C	D	E	F	G	H
9003067	3348044	12351111	10317036	11098540	8577287	8795599	7273497

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -15 (d) & 15 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि PMJDY योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 10317036 रूपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सूचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रूपे कार्ड में से केवल 8795599 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमें से भी अब तक केवल 7273497 खातों में रूपे कार्ड activate हो पाया है । बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless

transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपये कार्ड का activation करना अत्यंत जरूरी है , और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबंधित बैंकों से प्राप्त आंकड़ा पृष्ठ संख्या-16 (a) में दर्शाया गया है।

Status ason 31.03.2019:

No.of Claims	No.of Claims settled	No. of Claims Pending	No. of OD Facility given	Amt of OD Facility (Rs in Lacs)
474	431	43	136606	6086

प्रधानमंत्री जन-धन योजना” के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY	PMSBY	APY	
Total Enrolment	Total Enrolment	Enrolment during 18-19	Total Enrolment since inception
764555	3312250	258566	343762

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-16 (b) एवं 16 (c) सलग्न है)

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक सं	67

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबंधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दिनांक 31 मार्च 2019 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है :-

[राशि करोड़ में]

विवरण	31.03.2018	31.12.2018	31.03.2019	Variation over last FY
Advances	85518.63	94002.59	95562.14	10043.51
Gross NPA	5223.27	5657.68	5711.86	488.59
Provision	2790.54	2813.78	2820.73	30.19
Net N.P.A	2432.73	2843.90	2891.13	458.40
Percentage of Gross NPA	6.10%	6.01%	5.98%	(-)0.12%
percentage of Net NPA	2.84%	3.02%	3.02%	(-)0.18%

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। रु 5711.86 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.98% है, एक चिंताजनक आंकड़ा है।

(विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलग्रक के रूप में दर्शाये गए हैं।)

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 31 मार्च 2019 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qtr.		Cases disposed during last Qtr.		status as on 31.03.2019	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
133204	231.15	1211	29.99	1716	47.75	132699	213.39

(रिपोर्ट- annexure-20)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 31मार्च 2019 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 31.03.2019	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
2150	809.63	444	235.28	674	170.15	1920	874.76

(रिपोर्ट- annexure-21)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 31मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, SARFAESI cases की position निम्नवत है:

(Rs in Cr)

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession	Physical Possession taken	No. of cases pending at dist. level
A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	A/C	A/C
4458	1877.27	1963	858.52	601	70	531

(रिपोर्ट- annexure-22)

ध्यातव्य हो कि ऋणियों के नाम के साथ बैंको से प्राप्त जिलावार आंकड़ों के अनुसार केवल 150 cases physical possession हेतु जिलों के अधिकारियों के पास लंबित पड़े हैं। बैंको से बार बार आग्रह के बावजूद इस रिपोर्ट एवं पोर्टल के रिपोर्ट में काफी भिन्नता है जिसपर सभी बैंको द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। हालाँकि पूर्व में SLBC की बैठकों में दिए गए निर्देशानुसार SLBC द्वारा इन 150 cases की जानकारी राज्य सरकार को दे दी गयी है।

NB: SLBC द्वारा विभिन्न बैंको से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर PMEGP, KCC तथा PMMY योजनाओं के अंतर्गत दिए गए ऋण में NPA की स्थिति के आकलन का प्रयास किया गया है। यद्यपि बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ों में विसंगतिया है, परन्तु इन आंकड़ों के अध्ययन से NPA की बढ़ती समस्या का पता चलता है।

Scheme	No. of A/Cs	Amt of NPA (Rs in Cr)	% wrt advances in this sector
PMEGP	6994	120.20	32.45%
KCC	399736	1310.12	19.01%
PMMY	42121	736.82	18.29%

{रिपोर्ट पृष्ठ संख्या-18 (a) एवं 18 (b)}

कार्यसूची सं	8
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक सं	67

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत आवेदनों के ई-टैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने वेबसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं। इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है। SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक **31.03.2019** तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved
10255	266.98	1577	38.32	7393	188.58	1360	36.20

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 31.03.2019 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है)

8.2 NULM & PMAY

शहरी विकास विभाग से प्राप्त NULM से संबंधित बैंकवार प्रगति प्रतिवेदन (SEP-I) रिपोर्ट संख्या-19 (a) एवं PMAY से सम्बंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-19 (b) में दर्शायी गई है।

SEP-I & SHG (NULM) report as on 31.03.2019

Schemes	No. of applications forwarded to Bank	No. of applications sanctioned	No of applications disbursed	No of applications pending
SEP-I	1611	1204	1090	407
SHG	487	333	259	155

PMAY Report (31.03.2019)

Source	Application submitted/received during the FY	No. of application sanctioned	Amt Sanctioned	No. of application rejected	No. of applications pending
Govt	2184	887	179.17	311	989
Banks	1772	1750	339.60	7	15

कार्यसूची संख्या	9
बैठक की तारीख	15.05.2019
बैठक संख्या	67

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of 31.03.2019)
झारखंड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंकों के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित)		1 जिला

AFY 18-19 का वार्षिक लक्ष्य :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -573 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17110

उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -615 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17970

{ विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-20 (a)}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन - 10

भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण - 02

भवन निर्माण कार्य प्रगति पर - 12

भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी - 01

- बोकारो,चतरा,धनबाद,पूर्वी सिंहभूम, गुमला,खूंटी, कोडरमा,सिमडेगा,देवघर एवं सराइकेला में भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण हो गया है परन्तु सराइकेला में RSETI का कार्य नए भवन में प्रारंभ नहीं हो सका है |
- गिरिडीह एवं जामतारा में भवन निर्माण का कार्य लगभग समाप्ति पर है |
- रामगढ़ में निर्माण कार्य से सम्बंधित अंतिम निर्णय होना बाकी है |

(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-20 (b) से 20 (d) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थियों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2017-18 के दौरान		AFY 2018-19 के दौरान	
कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked	कुल प्रशिक्षनार्थी	Credit Linked
17660	2461	17970	1525

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-20 (e) एवं 20 (f) पर उपलब्ध है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (जिला स्तर पर)	संख्या
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	15
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर, पलामू	7
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	2

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र ;

वनांचल ग्रामीण बैंक - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 6 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सराइकेला –खरसावाँ) केंद्र का संचालन कर रही है ।

जनवरी-मार्च 2019 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	1328
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	3305
कुल	4633

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-21 (a) एवं 21 (b) पर उपलब्ध है}

RBI के दिशा निर्देश के अनुरूप reporting तिमाही के अंत में सभी FLC एवं उसके परिचालन के लिए अधिकृत अधिकारियों (Phone Nos.& E-mail Addresses) की जानकारी पृष्ठ संख्या-21 (c) में दी जा रही है ।

कार्यसूची सं	10
बैठक की तारीख	15.05.2019
बैठक संख्या	67

एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज
पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:
एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	उप समिति के नाम	उप समिति के पदधारी	उप समिति के अन्य सदस्य	संदर्भ	पिछली बैठक की तिथि
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2)नई परियोजना/स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	02.04.2019
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार	05.02.2019

			4) उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक 6) अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक-एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	11.01.2018
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव / सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9) यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	05.02.2019
5.	एसएलबीसी परिचालन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक	1) नवीनतम स्थिति और सरकार / बैंकों	12.11.2018

	समिति	संयोजक - एसएलबीसी	3) नाबार्ड 4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	के पास लंबित मुद्दे 2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक-एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	02.02.2015
7.	एमएसएमई और सरकार प्रायोजित योजनाओं पर उप-समिति	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक-बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	06.02.2019
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक-एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दे (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	07.11.2017
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन-झारखंड	20.11.2018

10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	20.11.2018
11	NPA पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, संस्थागत वित्त 2) एसएलबीसी 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8) यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 9) केनरा बैंक 10) UCO Bank	राज्य में NPA एवं recovery की स्थिति; DRT, Certificate एवं SARFAESI cases	05.02.2019

कार्यसूची सं.	11
बैठक की तिथि	15.05.2019
बैठक सं.	67

विविध कार्यसूची

1. हमारे राज्य में SUB SERVICE AREA (4178) को विभिन्न बैंको को आवंटित/चिह्नित करने का कार्य काफी काफी समय पूर्व हुआ है। इस बीच कई जिलों में नए ब्लॉक/प्रखण्ड का सृजन किया गया है। कई जिलों में उन प्रखंडों में SUB SERVICE AREA UPDATION का कार्य नहीं हुआ है। सितंबर महीने में एसएलबीसी द्वारा सभी एलडीएम से इस संबंध में सूची ली गई थी। कई जिलों की सूची अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण थी। इसके स्पष्ट निर्धारण के अभाव में इन इलाकों में बैंको द्वारा BC की नियुक्ति एवं अन्य योजनाओं के संचालन में कठिनाई आ रही है। इस कारण संबंधित विषय पर एक नए सिरे से कार्य करने की जरूरत के मद्देनजर 65th SLBC की बैठक में सभी एलडीएम से आग्रह किया गया था कि दिसम्बर माह के अंत तक BLBC मीटिंग कर जिले के सभी गाँव को उनके नजदीकी बैंक की शाखाओं को आवंटित कर दें और नव आवंटन की सूची एसएलबीसी को प्रेषित कर दें ताकि इसे सभी बैंको को उपलब्ध कराया जा सके और साथ ही एसएलबीसी के वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित किया जा सके। LDMs से अनुरोध किया गया था कि सभी गांवों को विभिन्न बैंको को आवंटित किये जाने का कार्य काफी सावधानीपूर्वक किया जाये और इसे BLBC की बैठक में अनुमोदित करा लिया जाये ताकि इस पर भविष्य में कोई असंतोष न हो। परन्तु अभी भी कई LDMs ने यह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया है। जिन LDMs ने यह exercise पूरा कर लिया है, उनसे अनुरोध है कि वे BLBC की बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कराकर SLBC को इससे सम्बंधित जानकारी अविलम्ब दे।

(Action: सभी सम्बंधित LDMs एवं बैंक)

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 17-10/2018-CSIS दिनांक 10.01.2019 के आदेश के आलोक में राज्य के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार SLBC द्वारा सभी बैंको से विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की जानकारी मांगी गयी थी। अद्यतन जानकारी रिपोर्ट 26 (a) एवं 26 (b) में सलग्न है। इससे विदित होता है कि इस दिशा में बैंको द्वारा पूर्ण रूप से प्रयास नहीं किया जा रहा है।

(Action: सभी बैंक)

कार्यसूची सं.	12
बैठक का दिनांक	15.05.2019
बैठक सं	67

Less cash/Digital बैंकिंग

- माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुड़े विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है। इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है। राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 31.03..2019 तक राज्य में कुल 34220 POS machines का installation कराया जा चुका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था। यद्यपि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतु इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 4.20 लाख credit card, 1.56 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 23.42 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है।
{प्रगति प्रतिवेदन सलग्न-पृष्ठ सं-27 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	15.05.2019
बैठक सं	67

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

अगली 68 वीं SLBC की बैठक की तारीख : 13 अगस्त 2019